भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4132
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

†4132. **श्री जगदम्बिका पाल**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 जैसी नीतियों के अंतर्गत शिक्षण पद्धति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका की परिकल्पना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित आकांक्षी जिलों में स्कूलों तक डिजिटल शिक्षा की सुलभता में सुधार हेतु कोई विशेष प्रावधान करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): भारत सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरू की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए प्रासंगिक चरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिज़ाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) आदि जैसे समकालीन विषयों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

एनईपी 2020 के विजन के अनुरूप, छात्रों को एआई से संबंधित कौशल से युक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा VI से 15 घंटे के कौशल मॉड्यूल के रूप में एआई प्रदान करता है। सीबीएसई कक्षा IXवीं से XIIवीं तक एआई को वैकल्पिक विषय के रूप में भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, दीक्षा (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) पहल के माध्यम से शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक पहल, दीक्षा ने एआई आधारित सुविधाओं को एकीकृत किया है, जैसे: वीडियो में एआई आधारित मुख्य-शब्द खोज की सक्षमता, जिससे वीडियो के भीतर प्रासंगिक अवधारणाओं को आसानी से फ़िल्टर किया जा सके, और रीड-अलाउड सुविधा, जिससे दृष्टिबाधित छात्रों को मदद मिल सके।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर की पहल एसओएआर (एआई रेडीनेस के लिए कौशल) शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12) में एआई जागरूकता और बुनियादी कौशल को समाहित करना और शिक्षकों में एआई साक्षरता का विकास करना है। एसओएआर में छात्रों के लिए तीन क्रमिक 15-घंटे के मॉड्यूल शामिल हैं–जागरूक होने के लिए एआई, अर्जित करने के लिए एआई और आकांक्षा रखने के लिए एआई और शिक्षकों के लिए एक स्वतंत्र 45-घंटे का मॉड्यूल, जिसका शीर्षक है शिक्षकों के लिए एआई। यह कार्यक्रम एआई की मूल बातों, जनरेटिव एआई, दैनिक जीवन में एआई, प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांतों, नैतिकता, साइबर सुरक्षा और भविष्य के करियर के अवसरों जैसी अवधारणाओं से परिचित कराता है।

तकनीकी शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने आईटी कार्यक्रमों में एआई से संबंधित विषयों को शामिल किया है। मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी गैर-कंप्यूटर विज्ञान शाखाओं के लिए विशेष एआई पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं ताकि उनके क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को एकीकृत किया जा सके। वर्ष 2021 में, एआईसीटीई ने एआई और डाटा विज्ञान के लिए एक आदर्श पाठ्यचर्या तैयार की। संकायों को नई तकनीकों से अवगत कराने में मदद करने के लिए, एआईसीटीई एआई और अन्य उभरते क्षेत्रों में संकाय विकास कार्यक्रम भी चला रहा है।

इसके अलावा, एआई ज्ञान और कौशल तक अभिगम्यता में सुधार के उद्देश्य से, शिक्षा मंत्रालय के स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने

आईआईटी, आईआईएससी जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 110 से अधिक मुफ्त एआई-संबंधित पाठ्यक्रम प्रदान किए हैं। आज की तिथि के अनुसार, 41.2 लाख से अधिक छात्रों ने इन पाठ्यक्रमों में नामांकन किया है।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ, स्वास्थ्य, संधारणीय शहरों और कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना का भी अनुमोदन दिया है। बजट वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में एक एआई उत्कृष्टता केंद्र का भी प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार ने "इंडियाएआई" मिशन की शुरुआत की है, जो देश के विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक सुदृढ़ और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की एक कार्यनीतिक पहल है। यह मिशन भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित है, जिसके लिए सात आधारभूत स्तंभों जैसे इंडियाएआई कंप्यूट केपेसिटी, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर (आईएआईसी), इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म, इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (आईएडीआई), इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, और सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है। समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा VI से XII वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

***